CIF IMPACT FACTOR:4.465

North Asian International Research Journal of Multidisciplinary

ISSN: 2454-2326 Vol. 5, Issue-2 February-2019

Index Copernicus Value: 58.12

A Peer Reviewed Refereed Journal

भारत में स्वास्थ्य सेवा का मूल्याकंन विशेष रूप से बिहार के सन्दर्भ में

*सुजीत कुमार शर्मा

*शोधार्थी (वाणिज्य संकाय)

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

पृष्ठभूमि

सेवा क्षेत्र भारत के सामाजिक –आर्थिक विकास की जीवनरेखा है। यह वर्तमान में देश का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है जिसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है और जो विश्वभर में उत्पादन बढ़ाने में योगदान कर रहा है। किसी अन्य क्षेत्र से कहीं अधिक लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। इस क्षेत्र के विकास के पीछे के कारण हैं – शहरीकरण, निजीकरण और मध्यवर्ती एवं अंतिम उपभोक्ता सेवाओं की बढ़ती मांग। उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं का होना अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं वैश्विक प्रर्वत्तियों से कदम मिलाते हुए भारतीय सेवा क्षेत्र मे भी काफी उछाल आया है और हाल के वर्षो में यह राष्ट्रीय आय और रोजगार दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला क्षेत्र बन गया है। भारत के जीडीपी में आधे से अधिक का योगदान सेवा क्षेत्र अथवा तृतीयक क्षेत्र का है। सेवा अथवा तृतीयक क्षेत्र मे व्यापार, परिवहन एवं संचार, वित्तीय सेवाएं, जमीन–जायदाद, पर्यटन, सॉफ्टवेयर उद्योग, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं आदि जैसी तमाम गतिविधियां सम्मिलित है। भारत के सेवा उद्योग में प्रमुख हैं – स्वास्थ्य और शिक्षा । ये देश की आर्थिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कर्मठ और अध्यवसायी मानव पूंजी के निर्माण में सहायक सिद्ध होगी।

सेवा क्षेत्र के विकास में, विशेषकर उदारीकरण के बाद, उल्लेखनीय तेजी आई है। इस क्षेत्र का योगदान कई अर्थो में काफी महत्वपूर्ण है। जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 55.2 प्रतिशत रहा है और यह 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा हैं जहां तक रोजगार का प्रश्न है, इसका एक –चौथाई सेवा क्षेत्र से है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी सेवा क्षेत्र का हिस्सा काफी ऊँचा है। निर्यात में एक–चौथाई इसी क्षेत्र से होता है। 2010–11 के पूर्वार्द्ध में 27.4 प्रतिशत की वृद्धि काफी तेज रही थी। भारतीय अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धिदर सम्मिश्र वार्षिक–सीएजीआर, जो नब्बे के दशक में 5.7 प्रतिशत थी, वह 2004–05 से 2009–10 की अवधि में बढ़कर 8.6 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। वृद्धिदर में यह तेजी काफी हद तक सेवा क्षेत्र में आई तेजी के कारण ही आई थी। सेवा क्षेत्र की विकास दर

1990 के दशक के 7.5 प्रतिशत से बढ़कर 2004–05से 2009–10 की अवधि में 10.3 प्रतिशत हो गई थी। सेवा क्षेत्र की विकास दर इसी अवधि में कृषि और उद्योग क्षेत्रों के सम्मिलित वार्षिक उत्पाद पर 6.6 प्रतिशत से अधिक तेज थी । यद्यपि कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का योगदान पिछले कुछ वर्षो में बढ़ रहा है जबकि प्राथमिक क्षेत्र के अंशदान में कमी आ रही है।

1951–2009 के अवधि में , जीडीपी और सेवा क्षेत्र में औसत वृद्धि दर दोगुने से कुछ ऊपर रही है, कृषि और उद्योग में दोगुने से कम विकास हुआ है। सेवा क्षेत्र की विकास दर 2005–06 से 10 प्रतिशत के आसपास ही रही है। यह समग्र जीडीपी विकास की तुलना में काफी अधिक है जो 2007–08 के 9.3 प्रतिशत से 2008–09 में गिरकर 6.8 प्रतिशत रह गई । यह कहा जा सकता है कि सेवा क्षेत्र की सक्षमता ने भारतीय अर्थव्यवस्था की सक्षमता में भी योगदान किया है। वर्ष 1991 से सुधारोत्तर अवधि में देश की उच्च विकास की यात्रा का मार्ग इसके तृतीय क्षेत्र, अर्थात सेवा क्षेत्र के शानदार और निरंतर ठोस प्रगति से ही प्रशस्त हुआ है। ऐसा इसलिए कि प्राथमिक (कृषि) और द्वितीय (विनिर्माण) क्षेत्र दोनों विकास काफी मंद रहा है। सेवा क्षेत्र निर्विवाद रूप से देश की समग्र प्रगति और सकल घेरलू उत्पाद (जीडीपी) का एक महत्वपूर्ण अंग रहा हैं।

साहित्य पुनरावलोकन

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) ने सेवा क्षेत्र का जो वर्गीकरण किया है, उसमें चार प्रमुख श्रेणियां बताई गई है। ये है: (1) व्यापार, होटल और रेस्तरां, (2) परिवहन, भंडारण और संचार (3) वित्तपोषण, बीमा, जमीन–जायदाद और व्यापारिक सेवाएं, तथा (4) सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं । इनमें से वित्तपोषण, बीमा, जमीन–जायदाद और व्यापारिक सेवाएं तथा व्यवसाय, होटल एवं रेस्तरां सबसे बड़ा समूह है। वर्ष 2009–10 की जीडीपी में इनका अंशदान क्रमशः 16.7 प्रतिशत और 16.3 प्रतिशत था। सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाओं की श्रेणी का अंश 14.4 प्रतिशत था जबकि परिवहन, भंडारण और संचार का हिस्सा 7.8 प्रतिशत था। सेवा क्षेत्र की सीमा पर विराजमान निर्माण उद्योग का अंश 8.2 प्रतिशत था। [1]

सरकारी रिपोर्टो में यह बताया गया है कि नब्बे के दशक से लेकर 2004–05 से 2009–10 की अवधि में समग्र विकासदर (सीएजीआर) में 5.7 से लेकर 8.6 प्रतिशत की जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वह काफी हद तक उसी अवधि में सेवा क्षत्र में 7.5 प्रतिशत से लेकर

10.3 प्रतिशत तक की वृद्धि के कारण हुई थी। सेवा क्षेत्र की विकास दर कृषि और उद्योग क्षेंत्रों की सम्मिलित विकास दर 6.6 प्रतिशत से भी तेज थी। वर्ष 2009–10 में सेवा क्षेत्र की विकास दर 10.1 प्रतिशत थी जबकि 2010–11 में 9.6 प्रतिशत (अग्रिम अनुमान) रही। विश्व व्यापार संगठन के ताजा आंकड़ो के अनुसार हाल के वर्षो में सेवा क्षेत्र देश का सबसे गतिशील क्षेत्र रहा है और यह 10 प्रतिशत की

औसत वार्षिक दर से बढ़ रही है। इस प्रकार इसकी विकास दर जीडीपी की दर से अधिक से अधिक रही है और यह दर्शाता है कि 2008 से शुरू हुए वैश्विक आर्थिक संकट पर इसका प्रभाव नकारात्मक रहा है। [2]

डब्ल्यूटीओ के अनुसार भारत सेवाओं का मुख्य निर्यातक देश है। परिवहन, यात्रा और व्यापारिक सेवाओं के क्षेत्र में हुए विकास के साथ ही सॉफ्टवेयर और आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) के क्षेत्र मे भी निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप जीडीपी के प्रतिशत के रूप में इस क्षेत्र का अंश 2006–07 के 3.1 प्रतिशत अर्थात 29.5 अरब अमरीकी डॉलर हो गया। परंतु 2008–09 में ऊँचाई चढ़ने के बाद भारत से सेवा क्षेत्र के निर्यात में कमी आई जोकि अंतरष्ट्रीय स्तर पर छाए वित्तीय संकट से प्रभावित थी। हालांकि सेवाओं के आयात में वृद्धि होती रही है। इससे 2009–10 मे जीडीपी के 2.8 प्रतिशत अर्थात 35.7 अरब डॉलर के बराबर अधिशेष में कमी आई । डब्ल्यूटीओ का मानना था कि 2010–11 के अधिशेष में 2008–09 से भी अधिक कमी आएगी। वैश्विक संकट से व्याापारिक सेवाओं और संचार पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा जबकि सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वृद्धि जारी रही। सर्वेक्षण का दावा है कि 2009 में राष्ट्रीय जीडीपी में सेवा क्षेत्र के 52 प्रतिशत और 2009–10 में 55.2 प्रतिशत योगदान को देखते हुए भारत की तुलना सबसे अधिक जीडीपी वाले विश्व के शीर्ष 12 देशों से की जा सकती है। चीन में जीडीपी में सेवा क्षेत्र का अंश केवल 39.2 प्रतिशत है जोकि अपेक्षाकृत काफी कम है, जबकि समग्र जीडीपी के मामले मे यह भारत से तीन गुणा अधिक है। सेवा क्षेत्र की विकासदर के लिहाज से चीन (10.5 प्रतिशत) भारत (8.9 प्रतिशत) से आगे है, और ये दोनों देश शीर्ष 12 देशों में से अधिकतर सेवा क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज करा रहे थे, केवल चीन (9.4 प्रतिशत) भारत (6.8 प्रतिशत) और ब्राजील (2.6 प्रतिशत) में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। यह इन देशों के सेवा क्षेत्र की आंतरिक दृढ़ता और प्रगति को प्रमाणित करता है।[3]

सरकारी रिपोर्टो में बिना किसी च्रक के यह बताया जा रहा है कि भारत सेवा क्षेत्र नीति निर्यात में वृद्धि की ओर अग्रसर है। वस्तुओं के विनिर्माण क्षेत्र की निर्यात वृद्धिदर हाल के वर्षो में अनिश्चित रही है। इसका कारण है वैश्विक मंदी और भारत के परंपरागत और गैर–परंपरागत व्यावसायिक भागीदारों के बीच संरक्षणवादी प्रवृत्तियों का बढ़ता दबाव। सर्वेक्षण रिपोर्ट भुगतान संतुलन आंकड़ो के हवाले से दर्शाती है कि 2004–05 से 2008–09 की अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में क्रमशः 22.2 प्रतिशत और 25. 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वैश्विक मंदी के कारण 2009–10 में सेवाओं की विकासदर में धीमापन आ गया, परंतु यह कमी वस्तुओं के निर्यात में आई गिरावट से कम थी और इसने 27.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2010–11 के पूर्वार्द्ध में ही तेजी से वापसी कर ली। इस बेहतर प्रदर्शन में कुछ सेवाओं ने भी योगदान किया। सॉफ्टवेयर एक ऐसा क्षेत्र है जिसके निर्यात मे भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के तौर पर अपनी छवि बनाई है। पर्यटन और यात्रा से संबंधित सेवाओं की भी भारत के सेवा क्षेत्र में प्रमुखता से गिनती होती है। उभरती और संभावनापूर्ण सेवाओं में अनेक पेशेवर सेवाएं अधोसंरचना से संबंधित सेवाएं और वित्तीय सेवाएं सम्मिलित है।

सेवा क्षेत्र से संबंधित सरकारी रिपोर्ट में सेवा क्षेत्र की अनंत गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए तृतीयक क्षेत्र के विशाल और अब तक अदोहित संभावनाओं पर जो जोर दिया गया है वह उचित ही है। अतः इस क्षेत्र के लिए बड़ी सावधानी से और विभिन्न

सेवाओं के लिए अलग–अलग विशिष्ट रणनीतियां तैयार करने की आवश्यकता है क्योंकि प्रत्येक सेवा क्षेत्र की अपनी शक्तियां भी हैं जिनसे वह आगे बढ़ सकता है और कमजोरियां भी है, जिनपर विजय पाना हैं। निस्संदेह सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्राद्योगिक जनित सेवाओं (आईटीईएस) तथा दूरसंचार जैसे सेवाओं में देश की स्पर्धात्मकता को बनाए रखने के विचार के बारे में पूरी सहमति है, क्योंकि इन क्षेत्रों मे भारत पहले ही नाम कमा चुका है। हमारे लिए अगला कार्य पर्यटन और जहाजरानी जैसे कुछ पारंपरिक क्षेत्रों में भी कदम बढ़ाने का है, जहां अन्य राष्ट्र पहले ही अपने को स्थापित कर चुके है। परंतु यहां और बेहतर तैयारियों की आवश्यकता है ताकि हम पर्यटकों की भीड़ को अपने यहां आने के लिए आकर्षित कर सकें और देश के गौण और प्रमुख बंदरगाहों पर उत्तम सुविधाएं निरंतर प्रदान कर सकें।

यूनिडो (2009) के शब्दो में कहें तो लगभग 200 वर्ष तक सेवा को ओछा, अकुशल और निम्नस्तर का प्रवर्तनवादी माना गया और आर्थिक विकास और संवृद्धि को श्रमसाधन (लेबर इंटेसिव) विनिर्माण क्षेत्र से जोड़कर रखा गया लेकिन आज सेवाएं अर्थव्यवस्था की सबसे क्रियाशील घटक का दर्जा प्राप्त कर चुकी है।[4] ऐसे में एक नीतिगत प्रश्न यह है कि गरीब देशों के लिए अर्थव्यवस्था का यह रूपांतरण किस सीमा तक सही है। गरीबी और बेरोजगारी के नीचे दबे जा रहे लोगों को बचाने का क्या यही सर्वाधिक उचित आधार है।

कुछ वैश्विक अध्ययन बताते हैं कि अधिकांश विकासशील देशों में सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि, रोजगार निर्माण और गरीबी निवारण में उद्योग और विनिर्माण की अपेक्षा अधिक योगदान हैं यही कारण है कि वैश्विक जीडीपी में सेवाओं का हिस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अध्ययनों पर विश्वास करें तो इस समय सेवाएं वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 25 प्रतिशत अधिक का योगदान कर रही हैं (विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में इसका हिस्सा औसतन 45 प्रतिशत है)। वैश्विक व्यापार में भी सेवाएं सबसे तेज गति से बढ़ने वाले क्षेत्र के रूप में स्थापित हो रही है जिनका सबसे ज्यादा लाभ इस समय विकासशील देश उठाते दिख रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 1990 में विकासशील देशों का सेवाओं के वैश्विक निर्यात में योगदान केवल 14 प्रतिशत था, जो वर्ष 2008 में बढ़कर 21 प्रतिशत हो गया। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पिछले दो दशको में विकासशील या गरीब देशों की सेवाओं का निर्यात वस्तुओं के निर्यात की अपेक्षा तेजी से बढ़ा है।

आईएमएफ द्वारा प्रदत्त आंकड़े बताते है कि लगभग सभी विकसित देशों में सेवा क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सा लगभग 75 प्रतिशत के आसपास है।[5] लेकिन एक अहम बात यह भी है कि पिछले लंबे अरसे से इन विकसित देशों में ही अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा हिचकोले खा रही है। अभी भी इन अर्थव्यवस्थाओं के सिर पर से यह संकट समाप्त नही हुआ है। संभव है कि दुनिया को एक ओर आर्थिक संकट का सामना जल्द ही करना पड़ जाए। एक ओर महत्वपूर्ण बात यह है कि 2008 में जब अमरीका में संकट आया था, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया ने महसूस किया, वह इसी तृतीयक क्षेत्र से पैदा हुआ था। आगे की स्थिति क्या होगी यह तो भविष्य बताएगा लेकिन अभी इन सेवा प्रधान देशों की हालत पर जरा नजर डालकर देखें तो तस्वीर काफी हद तक साफ नजर आएगी।

शोध समस्या का विवरण

स्वास्थ्य उद्योग विश्व अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र के रूप में उभरा है। वैश्विक उत्पादन और रोजगार के क्षेत्र में इसका योगदान काफी अधिक हैं रोजगार की संभावना और राष्ट्रीय आय में योगदान दोनों ही लिहाज से यह भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बृहद और काफी गतिशील अंग है। सकल घरेलू उत्पाद में 55.2 प्रतिशत अंशदान के साथ सेवा क्षेत्र का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में कई गुना है। प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे इस क्षेत्र का रोजगार क्षेत्र में योगदान करीब एक चौथाई है। व्यवसाय, परिवहन एवं संचार, वित्तीय रियल इस्टेट (जमीन–जायदाद) और व्यापारिक सेवाओं के साथ–साथ सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाओं जैसी अनेक गतिविधियां इसके विस्तृत दायरे में समाहित है।[6]

स्वास्थ्य सेवा प्रणाली देश की निदान, उपचार ओर रोग से बचाव तथा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का उन्नयन करने वाली प्रणाली को कहते हैं। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की विशेषता इसमें सन्निहित होती है कि किस प्रकार चिकित्सा सेवा को संगठित, वित्तपोषित किया जाता है। चिकित्सा सेवा के संगठन का संबंध उन विषयों से है कि कौन यह सेवा प्रदान करता है (यथा–प्राथमिक स्तर के चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक नर्से ओर वैकल्पिक चिकित्सक) और क्या वे व्यक्ति के रूप में छोटे समूहों, बड़े समूहों अथवा विशाल कार्पोरेट संगठनों के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस क्षेत्र के वित्तपोषण में शामिल है, चिकित्सा सेवाओं के लिए भुगतान कौन करता है, (यथा–सरकार, स्वयं–भुगतान, निजी बीमा कंपनियां आदि) और चिकित्सा सेवा पर कितना धन खर्च होता हैं सेवा–प्रदान का अर्थ है कि चिकित्सा सेवाएं कौन ओर कहां प्रदान की जा रही है (यथा–अस्पतालों में, चिकित्सकों के क्लीनिक में अथवा विभिन्न प्रकार के बाह्य रोगी औषधालयों में और ग्रामीण, शहरी और उपनगरीय क्षेत्र में)।

भारत की वर्त्तमान जनसंख्या 1.21 अरब है और यह 1.8 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रही है।[7] भारत की जनसंख्या 2030 तक चीन से भी आगे निकल जाने की संभावना है और तब वह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। भारत परंपरा से ही एक ग्रामीण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था रहा है। हमारे देश में लगभग तीन चौथाई लोग अभी भी गांवों में ही रहते है। भारत की अनुमानित 37 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे (तेंदुलकर समिति रिर्पोट) रहती है।[8] इसलिए यहां एक कार्यकुशल स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की भारी आवश्यकता है, जाकि उत्तम सेवा कम खर्च पर उपलब्ध करा सके। जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुए इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। इसी के साथ–साथ गरीबों और अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की भी अति आवश्यकता है क्योंकि वे व्यय–साध्य चिकित्सा सेवा का भार नहीं वहन कर सकते ओर इस प्रकार वे उससे वंचित ही रह जाएगें।

स्वास्थ्य क्षेत्र राजस्व के लिहाज से भारत के सबसे विशाल क्षेत्रों में से एक है और यह क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा हैं। नब्बे के दशक में भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र 16 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ रहा था। वर्त्तमान में यह क्षेत्र जीडीपी में 5.2 प्रतिशत का अंशदान कर रहा है।[9] भारत का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र बढ़कर 40 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँच जाने का अनुमान लगाया गया।

भारत में निजी स्वास्थ्य सेवा का क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र के रूप में उभरा है। चिकित्सकीय पर्यटन के देश में सबसे रोमांचक रूप में उभरने के फलस्वरूप निजी क्षेत्र भी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भारी निवेश कर रहा है।[10] भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए भारी अवसर बन रहे है। हाल के वर्षो में भारत की स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राज्यों के साथ मिलकर केन्द्र सरकार ने नितिगत एवं संस्थागत विकास के माध्यम से स्वास्थ्य संसाधनों के आवंटन और उपयोग में दक्षता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं की शुरूआत की है।

सरकार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में विदेशी/निजी निवेश को प्रोत्साहित कर रही है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक निर्धारित किए है और उन्हे लागू किया है। इसने निजी, सामाजिक और सामुदायिक बीमा के विकास में स्फुर्ति लाने का प्रयास किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकारी नीति चिकित्सकीय पर्यटन का समर्थन करती है। नीति विदेशी नागरिकों को भुगतान के आधार पर सेवा देने को निर्यात की तरह माना जाता हैं और उसे उन सभी वित्तीय प्रोत्साहनों के योग्य माना जाता है, जो निर्यात आय के लिए दी जाती है।[11] वीजा में एक नयी श्रेणी 'मेडिकल वीजा' शामिल की गई है जो भारत में इलाज करने के इच्छुक विदेशी नागरिकों को दिया जा सकता है। भारतीय कार्पोरेट अस्पतालों को अंतर्राष्ट्रीय अभिमान्यता योजनाओं के अंतर्गत प्रमाणित किया जा रहा है ताकि वे अपने को उत्तम गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा के प्रणेता के रूप में विदेशों में प्रचारित कर सकें। सरकार ने अपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग चिकित्सा उपकरण बाजार के प्रचार और सवंर्धन के लिए कुछ कदम उठाए हैं। नब्बे के दशक के मध्य में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरूआत के बाद निर्यात की स्थितियों में पर्याप्त सुधार हुआ है। आयात के लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया हैं। बहुसंख्यक स्वामित्व वाली सहायक कंपनिया अब खोली जा सकती है और लाभांश का भुगतान विदेशों में किया जा सकता है। चिकित्सा के उपकरणें के निर्माण में भारत को एक ठोस प्रतिस्पर्धी के रूप में पेश करने के लिए सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया है। प्रस्तुत अध्ययन में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के योगदान का मूल्यांकन किया गया । हमने विशेष रूप से बिहार के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का संदर्भ लिया है।

अध्ययन का उद्देश्य

इस अध्ययन का उद्देश्य :

1. भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के योगदान का आकलन करना,
2. भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का विकास एवं इसकी उभरती प्रवृतियों कों रंखाकित करना,
3. स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में किए जा रहे सरकारी प्रयासों की समीक्षा करना,
4. बिहार के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना तथा
5. अन्य सम्बद्ध समस्याओं का विवेचन करना है।

प्राक्कल्पना

हमारा अध्ययन निम्नांकित प्राक्कल्पनाओं पर आधारित रहाः

प्राक्कल्पना 1 : सेवा क्षेत्र के विकास में विशेषकर उदारीकरण के बाद उल्लेखनीय तेजी आई है।

प्राक्कल्पना 2 : हाल के वर्षो मे यह राष्ट्रीय आय और रोजगार दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला क्षेत्र बन गया है।

प्राक्कल्पना 3 : भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए भारी अवसर बन रहे हैं।

शोध प्रणाली

यह अध्ययन विश्लेषणात्मक प्रकृति का है और इसमे भारत का विकास के उच्च मांग पर स्थापित करने की परिकल्पना को साकार करने में सेवा क्षेत्र के योगदान तथा देश की समग्र प्रगति का आधार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विकास, उपलब्ध सुविधाओं, किए जा रहे सरकारी प्रयासों, सहयोग की प्रवृतियों के साथ–साथ भावी चुनौतियों का विश्लेषण किया गया।

अध्ययन के लिए आवश्यक आंकड़े प्रमुखतः द्वितीयक समंकों की सहायता से एकत्रित किए गए। द्वितीयक आँकड़े का प्रमुख स्रोत

- सरकारी प्रकाशन
- पत्र–पत्रिकाऐं
- समाचार पत्र
- पुस्तकें एवं
- इन्टरनेट इत्यादि रहा।

उपलब्ध समंको की सहायता से विश्लेषणत्मक अध्ययन किया गया । इसमें गणितीय तथा सांख्यिकीय पद्वतियों की मदद ली गई यथा –

- प्रतिशत,
- अनुपात एवं समानुपात,
- माध्य,

- प्रवृति विश्लेषण,
- विचलन,
- प्राक्कलन परीक्षण इत्यादि।

समंको का विवेचनात्मक अध्ययन/निर्वचन किया गया और उनका समावेश उपयुक्त अध्याय के अंतर्गत किया गया।

निष्कर्ष

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कतिपय प्रवृतियां देखी गई हैं। यदि उनपर उचित ध्यान दिया जाए तो उसके परिणाम उपयोगी हो सकते हैं। इसी तरह सभी दिशा में विकास के बीच यह क्षेत्र आन्तरिक और बाह्य चुनौतियों से जूझ रहा है।

सन्दर्भ :

1. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार की वेबसाइट– www.mospi.gov.in
2. विश्व व्यापार संगठन की वेबसाइट – www.wto.org
3. वही
4. www.unnido.org
5. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वेबसाइट – www.imf.org
6. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार की वेबसाइट – www.mospi.gov.in
7. भारत की जनगणना के आंकड़े – www.censusindia.gov.in
8. तेंदुलकर समिति रिर्पोट, 2005
9. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार की वेबसाइट – www.mospi.gov.in
10. अवस्थी, शालिनी (2015), स्वास्थ्य पर्यटन –नया आयाम, योजना, वर्ष 59, अंक 5, मई, पृष्ठ 49–51
11. www.incredibleindia.org